

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री बी०एल०मेहरड़ा, आर०ए०एस०)

अपील संख्या:—375 / 2015 / 223(2015 / 00118)

1. नौरत पुत्र सूरजमल उर्फ सूजा, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. मोहन पुत्र सूरजमल उर्फ सूजा, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. रतन पुत्र सूरजमल उर्फ सूजा, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरया उर्फ भंवरलाल पुत्र धूला, जाति माली, निवासी रामसर, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. छोटू पुत्र धूला, जाति माली, नि० रामसर, तह० नसीराबाद, जिला अजमेर.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 31.7.2015 वाद संख्या 87 / 2015 .

उपस्थित:—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. श्री सीताराम रावत, वकील रेस्पों संख्या 1 व 2
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पों संख्या 3 .

निर्णय

दिनांक:—16.4.2019

1. यह अपील विद्वान अपर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पों संख्या 1 व 2 द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष खाता संख्या 1149/20173 के कुल किता 34 का कुल रकबा 2.77 है० जो कि ग्राम रामसर, तहसील नसीराबाद में स्थित है बाबत् धारा 53 व 188 राज०काश्त०अधि० के तहत प्रस्तुत किया जिसमें अधी०न्याया० ने दिनांक 31.7.2015 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्याया० में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को तलब किया गया । रेस्पों के उपस्थित होने तथा अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । [वादीगण/रेस्पों](#) संख्या 1 व 2 के द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) की भूमि बाबत् राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र में अनुतोष संख्या 1 यह चाहा गया कि वादीगण को खातेदारी उद्घोषणा कर बंटवारा की आज्ञाप्ति पारित की जावे एवं अनुतोष संख्या 2 में [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जाकर पाबंद किया जावे । इस आशय का वाद दिनांक 13.7.2015 को प्रस्तुत किया जिस पर अधी०न्याया० ने बिना जांच रिपोर्ट करवाये एवं वादपत्र को बिना दर्ज रजिस्टर किये तथा वादपत्र के सम्मन की बिना तामील कराये ही अधी०न्याया० ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वादपत्र की विधि अनुसार सूचना जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को दी जानी चाहिये तथा तलबी पूर्ण होने पर जवाब दावा प्राप्त कर वाद में तनकियात कायम कर बाद साक्ष्य सुनवाई निर्णय पारित किया जाना चाहिये किन्तु अधी०न्याया० उक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2015 निरस्त की जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2008 (1) पेज 825 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।
5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है । अधी०न्याया० ने विभाजन की डिक्री पारित की है । यदि अपीलांट को कोई ऐतराज थे तो अधी०न्याया० के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे । बंटवारे की डिक्री में क्या त्रुटि है इस संबंध में अपीलांटस ने कोई कथन नहीं किया है । अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।
6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि [वादीगण/रेस्पों](#) संख्या 1 व 2 द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष अपीलाधीन भूमि के संबंध में दिनांक 31.7.2015 को वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी०न्याया० ने वाद को दर्ज रजिस्टर किये बिना तथा [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) को वाद के सम्मन जारी किये बिना प्रथम पेशी पर ही [वादीगण/रेस्पों](#) के वाद में निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.7.2015 को पारित की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाना चाहिये तथा प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण होने पर जवाबदावा प्राप्त कर वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये किन्तु अधी०न्याया० ने वाद को निर्णित करने में विधिक प्रक्रिया को पूर्णतया दरकिनार करते हुए प्रथम पेशी पर ही [प्रतिवादीगण/अपीलांटस](#) की तामील कराये बिना तथा साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी०न्याया० का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2015 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी०न्याया० को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है । विद्वान

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होता है ।

7. अतः अपील अपीलान्टस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.7.2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीन न्यायाधीश को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में अपीलान्टस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी०एल०मेहरड़ा)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर